



मेकल मीमांसा

अंतर-अनुशासनात्मक डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड यूजीसी केयर सूचीबद्ध अर्धवार्षिक शोध पत्रिका
वर्ष-15, अंक-02
जुलाई-दिसम्बर - 2023



इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय
अमरकंटक (म.प्र.)

कुलगीत

तपोभूमि यह ऋषि मुनियों की अति पावन अभिराम।
विद्या के आलोक पुंज को शत शत बार प्रणाम॥

यहाँ नर्मदा की लहरों में संस्कृति का अनुप्रासा।
यह भारत की अमर संपदा का पूरा इतिहास॥
यह स्कंदपुराण निरूपित अद्भुत रेवाखण्ड।
युग युग से महिमामंडित यह वंदित और अखंड॥
जनजातीय समाज यहाँ पर कर्मशील निष्काम।
विद्या के आलोक पुंज को शत शत बार प्रणाम....॥

यहाँ नर्मदा, सोन, जोहिला और अरण्डि प्रवाहित।
विद्या की देवी की पावन वीणा यहाँ स्वरासित॥
आदि शंकराचार्य, कपिल ने यहीं किया था ध्यान।
साधक, संत, कबीर पा रहे प्रज्ञा का वरदान॥
यहीं विश्व की मानवता को मिल पाता विश्राम।
विद्या के आलोक पुंज को शत शत बार प्रणाम....॥

यहाँ सुलभ है जनजीवन की परिपाटी का ज्ञान।
भारत की भाषा परिभाषा का अद्भुत अनुमान॥
यहाँ सूक्ष्म स्थूल दीखता, कण-कण ऊर्जावान।
मेघदूत सर्वदा निहारे साल, चीड़, वट, आम॥
सदा अमरकण्टक में गुंजित दिव्य सदाशिव नाम।
विद्या के आलोक पुंज को शत शत बार प्रणाम....॥

इस अंचल से जुड़ी हुई हैं जन-जीवन की आशा।
पूर्ण करेगा विद्यासागर जन-जन की अभिलाषा॥
वन औषधि की प्रचुर संपदा का यह सुंदर कोष।
संस्कृति और जीवन मूल्यों का यह करता उदघोष॥
यहाँ सिद्धि की सतत् चेतना बहती है अविराम।
विद्या के आलोक पुंज को शत शत बार प्रणाम....॥

यह धर्म भूमि, यह कर्म भूमि, जीवन दर्शन की मर्म भूमि।
यह ज्ञान भूमि, यह ध्यान भूमि, यह सतत् लक्ष्य संधान भूमि॥
यह बोध भूमि, यह शोध भूमि, यह “चरैवेति” अनुरोध भूमि।
यह तत्व भूमि, यह सत्व भूमि, यह मेधा की अमरत्व भूमि॥
गुप्त नर्मदा से अभिसिंचित विश्व विदित गुरुधाम.....

तपोभूमि यह ऋषि मुनियों की अति पावन अभिराम।
विद्या के आलोक पुंज को शत शत बार प्रणाम....॥

प्रोफेसर श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी

कुलपति
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक
(म.प्र.)

वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा (बुद्ध पूर्णिमा)

मेकल मीमांसा

अंतर-अनुशासनात्मक डबल ब्लाईंड पीयर रिव्यूड यूजीसी केयर सूचीबद्ध अर्धवार्षिक शोध पत्रिका
वर्ष-15, अंक-02 जुलाई-दिसम्बर - 2023

संरक्षक

प्रोफेसर श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी

कुलपति

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश

प्रधान सम्पादक

डॉ. राघवेन्द्र मिश्रा, प्रोफेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग

कार्यकारी सम्पादक

डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार राउत, प्रोफेसर, शिक्षा शास्त्र विभाग

सम्पादक मण्डल

डॉ. एन सुरजीत कुमार, प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान और मानवाधिकार विभाग

डॉ. गौरी शंकर महापात्र, सह-प्राध्यापक, जनजातीय अध्ययन विभाग

डॉ. ललित कुमार मिश्र, सह-प्राध्यापक, मनोविज्ञान विभाग

डॉ. नीरज कुमार राठौर, सह-प्राध्यापक, संगणक विज्ञान विभाग

डॉ. ऋषि पालीवाल, सह-प्राध्यापक, भैषजिक विज्ञान विभाग

डॉ. राहिल यूसुफ ज़ई, सह-प्राध्यापक, व्यवसाय प्रबंध विभाग

डॉ. बिमलेश सिंह, सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग

डॉ. हरजीत सिंह, सहायक प्राध्यापक, भाषाविज्ञान विभाग

डॉ. पूनम पांडेय, सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग

डॉ. आशुतोष कुमार, सहायक प्राध्यापक, भूविज्ञान विभाग

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय

अमरकंटक, मध्य प्रदेश

सहयोग राशि: 300.00

प्रकाशक :

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय,
अमरकंटक, मध्य प्रदेश- 484887
<http://www.igntu.ac.in/mekalmimansa.aspx>

मुद्रक:

वाइकिंग बुक्स
G-13, एस.एस. टावर
धम्मानी स्ट्रीट, चौरा रास्ता
जयपुर, राजस्थान- 302003

डिज़ाइन:

न्यू विजन एंटरप्राइजेज

ध्यानार्थ:

मेकल मीमांसा राष्ट्रभाषा हिंदी में गुणवत्तापरक एवं मौलिक शोधपत्रों के प्रकाशन के माध्यम से ज्ञान के प्रदीपन और विस्तार हेतु संकल्पित है। मेकल मीमांसा डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू पद्धति का अनुसरण करती है। पत्रिका लेखकीय गरिमा का सम्मान करती है। पत्रिका में प्रकाशित विचार और विश्लेषण लेखकों द्वारा प्रस्तुत हैं जो विषयवस्तु की मौलिकता एवं प्रमाणिकता हेतु उत्तरदायी हैं।



कुलपति जी का सन्देश

माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प विकसित भारत@2047 से हम सभी उत्साहपूर्वक समर्पित भाव से संबन्ध हो रहे हैं। देश और व्यक्ति का विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाल के वर्षों में भारत सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' जैसे संकल्प के साथ एक भारत-श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को स्वतंत्रता आन्दोलन से उपजे तथा हमारी सनातन संस्कृति में समाहित एकता तथा सामाजिक समरसता जैसे मूल्यों के साथ साकार करने की दिशा में स्वावलंबन, उद्यमशीलता, समावेशी विकास, सशक्तिकरण एवं निर्बलतम के उत्थान जैसे उद्देश्यों से परिपूर्ण नवोन्मेषी नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों के माध्यम से साकार करने का कार्य किया है। सरकार का यह प्रयास धरातल पर भी परिलक्षित हो रहा है एवं इससे विकास की असमानता को दूर करने में भी सहायता मिल रही है। देश को विकसित करने का संकल्प शोध एवं नवोन्मेष को बढ़ाना, सामाजिक विकास, विभेदों के निर्मूलन, मानव विकास सूचकांक में सुधार और सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना से सिद्ध होगा। शोध और उच्च शिक्षा का संवर्धन विकास के दो महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हैं। शोध पत्रिकाएं नवोन्मेष को बढ़ावा देने, स्तरीय शोध को प्रोत्साहित करने एवं विश्लेषणात्मक दृष्टि को विकसित करने का काम करती हैं और शोधार्थियों को अपने शोध से दुनिया को परिचित कराने का मंच प्रदान करती हैं।

मेकल मीमांसा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रभाषा हिंदी में प्रकाशित होने वाली अर्धवार्षिक शोध पत्रिका है जिसका उद्देश्य जनजातीय, सामाजिक एवं राष्ट्रीय विमर्श को वैविध्य के साथ विस्तार देना है। पत्रिका ने निरंतरता के साथ ज्ञान की विविध शाखाओं में हो रहे शोध को प्रकाशित करने का महत्वपूर्ण कार्य मानक के अनुरूप किया है। मेकल मीमांसा राष्ट्रभाषा हिंदी में बहुविषयक, अंतर्विषयक शोध को बढ़ावा देती है एवं मौलिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, कला, दर्शन, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, प्रबंधन एवं वाणिज्य, संचार आदि सभी विषयों से शोध पत्रों को स्वीकार करती है। पत्रिका द्वारा पीयर रिव्यू पद्धति का अनुपालन किया जाता है एवं शोध पत्रों का मूल्यांकन निर्धारित मानदंडों के अनुरूप होता है। इस प्रकार पत्रिका में शोधपत्रों के चयन एवं प्रकाशन की प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तय मानकों के अनुरूप है। प्रस्तुत अंक में भी अनेक विषयों से लेख आए हैं और मुझे विश्वास है कि प्रकाशित शोध पत्र ज्ञान के क्षेत्र में रचनात्मक एवं उपयोगी योगदान करने में सक्षम होंगे। मेकल मीमांसा शोध पत्रिका के संपादक मंडल को समर्पित भाव से इसके निरंतर प्रकाशन के लिए मैं बधाई देता हूँ एवं आशा करता हूँ कि जुलाई-दिसम्बर 2023 अंक पठनीय तथा संग्रहणीय होने के साथ ही विमर्श को नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होगा।

समस्त संपादक मंडल को आगामी अंकों हेतु शुभकामना सहित

प्रोफेसर श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी
कुलपति

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय
अमरकंटक, मध्य प्रदेश

(iii)

मेकल मीमांसा

अंतर-अनुशासनात्मक डबल ब्लाईंड पीयर रिव्यूड यूजीसी केयर सूचीबद्ध अर्धवार्षिक शोध पत्रिका
वर्ष 15, अंक-02

जुलाई-दिसम्बर - 2023

इस अंक में

क्रम संख्या	लेख का शीर्षक	योगदानकर्ता	पृष्ठ संख्या
1.	भारत छोड़ो आंदोलन में बैतूल जिले का अवदान	डॉ. संकेत कुमार चौकसे	1-5
2.	अहोम जनजाति की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन (1526-1707)	डॉ रामेश्वर मिश्र	6-14
3.	भारत की G20 और ब्रिक्स में भूमिका	डॉ. ब्रजेश कुमार मिश्र डॉ. आलोक कुमार	15-24
4.	भारतीय अर्थव्यवस्था में जीएसटी का प्रभाव: पूर्व और पश्चात की राजस्व वृद्धि का अध्ययन	अमित गुप्ता प्रो. शैलेन्द्र सिंह भदौरिया	25-30
5.	कोविड-19 का जनमाध्यमों की भाषा एवं संचार पर प्रभाव (समाचारपत्रों के सन्दर्भ में)	अरविंद कुमार सिंह	31-45
6.	भारत में ओटीटी मनोरंजन विस्तार का विश्लेषणात्मक अध्ययन	विनोद वर्मा प्रो. राघवेंद्र मिश्रा	46-56
7.	शिक्षा सूचकांक (माता-पिता की शिक्षा) का स्नातक स्तर के छात्रों की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा पर प्रभाव का अध्ययन	आदित्य प्रकाश डॉ. आर. हरिहरन	57-65
8.	संथाल जनजाति के सशक्तिकरण में सामुदायिक रेडियो का योगदान	डॉ. अख्तर आलम उमेश शर्मा	66-77
9.	भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की दृष्टि, उद्देश्य और मूल्य विवरण का विश्लेषण	अक्षत चोपड़ा डॉ. आशिमा	78-92
10.	स्वातंत्र्योत्तर भारत में राष्ट्रीय अस्मिता का मूर्त विकास: पुरातत्व, कलाकृति एवं धरोहर	आकाश कुमार श्रीवास्तव डॉ. विनीता चंद्रा	93-100
11.	सतपुड़ा मेकल प्रदेश की जनजातीय परम्पराएँ : चिकित्सा पद्धतियाँ एवं स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में	डॉ. आशीष चाचौदिया डॉ. दुर्गेश कुर्मी	101-109
12.	समाज में विकास की संभावनाएँ : विशेष संदर्भ- रामकथा और कृष्णकथा	प्रो. रेनू सिंह	110-116

13.	सामाजिक चेतना का कवि धूमिल	अंकिता सिंह डॉ. जितेन्द्र कुमार सिंह	117-125
14.	आयुष चिकित्सा पद्धतियाँ और लोक चिकित्सा: एक मानवशास्त्रीय विवेचना	महेंद्र कुमार जायसवाल	126-136
15.	भारत में जल संकट का महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव : एक विश्लेषण	अनु डॉ रमेश कुमार	137-144
16.	ऊर्जा कूटनीति: भारत के आर्थिक विकास की कुंजी	स्निग्धा त्रिपाठी	145-158
17.	वनाश्रित जनजातीय जीवन में महिलाओं की भूमिका	मंजुला वर्मा भगवंता सिंह बघेल चिंतामणि टांडिया शिवाजी चौधरी	159-170

भारत की G20 और ब्रिक्स में भूमिका

डॉ. ब्रजेश कुमार मिश्र*

डॉ. आलोक कुमार**

सारांश

21वीं सदी के दूसरे दशक की बदलती हुई भू-राजनीतिकी, भू-सामरिक स्थिति एवं भू-आर्थिकी ने पूरी दुनिया को अपनी नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने पर विवश किया है। जब शक्ति-राजनीति के साथ ही बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में स्वयं को सुपर पावर बनाने की होड़ विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य लगी हुई है तो इस बात का आकलन करना समीचीन प्रतीत होता है कि भारत की स्थिति क्या है? वर्ष 2023 के दो बड़े आर्थिक फोरम की बैठक ने दुनिया को काफी प्रभावित किया है। यह फोरम हैं - ब्रिक्स और G-20। इन दोनों संगठनों की प्रकृति सैद्धांतिक तौर पर भले ही एक जैसी दिखाई पड़ती हो लेकिन यह दोनों अन्तर्राष्ट्रीय जगत को अपने-अपने तरीके से प्रभावित करते हैं। संयोगवश भारत इन दोनों संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है। भारत के लिए दुविधा यह है कि वह ग्लोबल साउथ की आवाज इन दोनों मंचों से एक ही साथ कैसे उठाए? साथ ही इन संगठनों में अपने कद में किस प्रकार वृद्धि करे? प्रस्तुत शोध पत्र में G-20 और ब्रिक्स का वैश्विक राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव, चुनौतियों और अवसर का अवलोकन किया गया है। इस पत्र का केन्द्रीय विषय, भारत की ब्रिक्स और जी-20 में भूमिका और सम्भावनाओं पर अवलंबित है। बदलते संदर्भों में भारत इन दोनों संगठनों के साथ किस प्रकार का सम्बन्ध स्थापित करते हुए अपने पुराने मित्रों (गुट-निरपेक्ष देश) के लिए किस प्रकार नए अवसर प्रदान करेगा और अपने विश्व गुरु की भावी दृष्टि से किस प्रकार न्याय कर सकेगा, का अवलोकन किया गया है।

बीज शब्द : ब्रिक्स, G-20, ग्लोबल साउथ, आर्थिक मंदी, जी.डी.पी.

प्रस्तावना

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वैश्विक राजनीति में शक्ति की राजनीति की अवधारणा में व्यापक परिवर्तन आया। यह आभासी शक्ति के रूप में प्रकट हो रहा था। सारी परिस्थितियाँ युद्ध जैसी थीं लेकिन इस तनाव के बावजूद भी स्थितियाँ नियंत्रण में रहीं। 1970 के दशक में “आत्मनिर्भरता के सिद्धांत” ने राष्ट्रों के मध्य सम्बंधों की नई परिभाषा गढ़ी। कोहेन और जोसफ नाई ने कहा था कि अब उच्च राजनीति की भांति निम्न राजनीति का विशिष्ट महत्व है। इसलिए सम्प्रति वैश्विक राजनीति में सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को वरीयता दी जानी चाहिए। यद्यपि इस सिद्धांत के प्रतिपादन के पूर्व ही कई क्षेत्रीय संगठन अस्तित्व में आ चुके थे, जो सिर्फ आर्थिक आधार पर एकजुट हुए थे। जिनका मूल उद्देश्य अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना था। 1990 के दशक तक आते-आते पूंजीवाद ने पूरी दुनिया में अपने पांव पसार लिए थे। सोवियत संघ के विखंडन के बाद अमेरिका एक मात्र शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका था। 1990 के दशक के मध्य में पूर्वी एशिया की आर्थिक राजनीति में भूचाल आ गया। इसी के परिणाम स्वरूप G-20 की नींव पड़ी किन्तु यह संगठन वस्तुतः अमेरिका में आयी आर्थिक मंदी के बाद ही अपना मूर्त

*सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान (मानविकी विभाग), श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

**सहायक प्राध्यापक (अतिथि), राजनीति विज्ञान (मानविकी विभाग), श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

रूप ले सका। सन 2023 में हुए दिल्ली शिखर सम्मेलन ने G-20 को G-21 की ओर मोड़ दिया। अब यह संगठन विकसित देशों के साथ ही तीसरी दुनिया के देशों अर्थात् ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करने के लिए उद्यमशील है।

G-20 के फोरम पर सिर्फ आर्थिक चर्चा ही नहीं होती है वरन जलवायु-परिवर्तन, ऊर्जा- संकट और आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। जी-20 की भांति ही एक और संगठन 21वीं सदी के उत्स पर उभरा जो विश्व की 40% जनसंख्या और चार महाद्वीपों के पांच देशों का प्रतिनिधित्व करता है। यह संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था को भविष्य में प्रभावित करने वाले अनुमान के कारण अस्तित्व में आया। दूरदर्शी जिम ओ नील ने “BRIC” की कल्पना 2001 में की और पुनः यह संगठन 2010 में ब्रिक्स के रूप में तब्दील हो गया। वर्तमान समय में यह संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था के जरिए पश्चिम के प्रभुत्व वाली वैश्विक राजनीति को चुनौती दे रहा है। ब्रिक्स देशों में बढ़ता विदेशी निवेश, प्रौद्योगिकी और नेतृत्व की अद्भुत क्षमता, सेवाओं और वस्तुओं के बढ़ते व्यापार की वजह से इसका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है जिसने इसे पश्चिमी अर्थव्यवस्था और उसके प्रमुख आर्थिक संगठनों जैसे कि G-7, G-20 और यूरोपीय यूनियन की पंक्ति में ला खड़ा किया है। वर्तमान समय में जब विश्व में नए समीकरण या दूसरे शब्दों में कहें कि “नव शीत युद्ध” जैसी स्थिति बनी हुई है तो वैश्विक फलक पर “ब्रिक्स” अपनी एक अलग पहचान बनाने को आतुर है। यही कारण है कि तीसरी दुनिया के देश अपनी आर्थिक व्यवस्था और अपनी सामान्य समस्याओं (जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संकट जैसे मुद्दों) को सुलझाने हेतु ब्रिक्स से जुड़ रहे हैं (Abrams, 2022)। इसने ब्रिक्स को नए कलेवर में दुनिया के समक्ष पेश किया है। सन 2023 के जोहान्सबर्ग में हुए सम्मेलन में 6 नए सदस्य देशों को जोड़ना ब्रिक्स के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। अब यह संगठन जनवरी 2024 से ब्रिक्स प्लस के रूप में परिणत हो जाएगा (Global Times, 2023)।

ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था उतार-चढ़ाव के दौर से गुजर रही है। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी दुनिया युद्ध की चपेट में हैं। अफ्रीकी महाद्वीप अशांत है। तब G-20 और ब्रिक्स जैसे संगठनों की भूमिका और भी बढ़ जाती है। भारत चूँकि दोनों संगठनों का हिस्सा है, इसलिए वर्तमान स्थिति में उसकी क्या भूमिका होगी यह विमर्श का विषय है?

वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स की भूमिका

21 वीं सदी की शुरुआत में ही वैश्विक फलक पर विकाशशील देशों ने आर्थिक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करनी आरंभ कर दी। इस क्रम में ब्राजील, भारत, चीन और रूस प्रमुख हैं। इन देशों की अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव हो रहा था। इनका प्रभाव स्पष्ट तौर पर इन देशों की राजनीति के साथ ही साथ वैश्विक जगत पर भी पड़ रहा था। इन देशों के सकल घरेलू उत्पाद को दृष्टिगत रखते हुए यह कहा जाने लगा कि आने वाले समय में यह दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था ब्रिक्स देशों की होगी। 2010 तक आते-आते राष्ट्रों के इस क्रम में दक्षिण अफ्रीका को भी सम्मिलित कर लिया गया। इन देशों की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि कोई भी विश्लेषक इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाने के विषय में नहीं सोच सकता था किन्तु वस्तुतः यह संभव हो सका अमेरिकी अर्थशास्त्री जिम ओ नील की परिकल्पना के चलते जिसने “बिलिडिंग बेटर इकॉनॉमिक ब्रिक्स” शीर्षक से एक शोध पत्र में यह कल्पना की कि ब्राजील, भारत, चीन और रूस पश्चिम के आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती देंगे। अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने इन देशों के

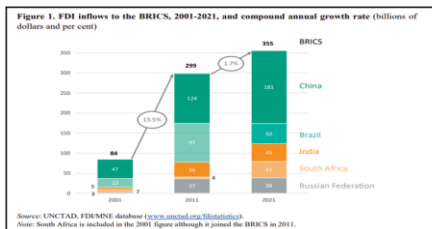
भारत की G20 और ब्रिक्स में भूमिका

लिए सम्मिलित रूप से “BRIC” कहा। 2003 में प्रस्तुत अपनी थीसिस “Dreaming with BRICs : The Path to 2050” में उसने भविष्यवाणी की थी कि 2050 तक इनकी अर्थव्यवस्था 6 बड़ी औद्योगिक देशों से बड़े हो जाएगी, फलतः यह संघ वैश्विक-अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभुत्व जमा लेगा (Tripathi, 2021)।

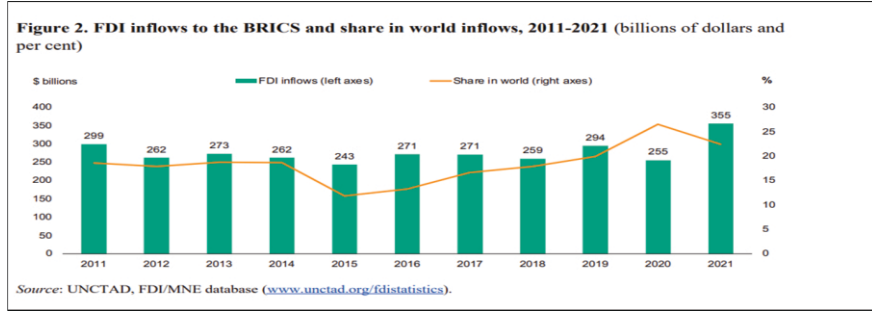
इन देशों की पहली औपचारिक बैठक सन 2006 में न्यूयॉर्क में हुई, जिसमें सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। इसके बाद सन 2009 में येकातेरिनबर्ग (रूस) में पहला BRIC शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया जहां इस बात पर चर्चा हुई कि दूसरे देशों को भी इस संगठन में शामिल किया जाना चाहिए। फलतः दक्षिण अफ्रीका इस संगठन में सम्मिलित हुआ और वर्ष 2011 में चीन में आयोजित होने वाले सम्मेलन में उसने भाग लिया (Sharma, 2019)। दिल्ली शिखर सम्मेलन ने इसमें 6 अन्य देशों को जोड़ने कि पेशकश की है। अब यह संगठन जनवरी 2024 से “BRICSPlus” के नाम से जाना जाएगा (Bhatt, 2023)।

ब्रिक्स देशों में 24 दिसम्बर 2010 को दक्षिण अफ्रीका के सम्मिलित होने के बाद इस संगठन का नाम ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स ब्राजील, भारत, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका का एक ऐसा साझा मंच है जो समान पहचान और सहयोग संस्थाकरण हेतु प्रयासरत है। यह एक ऐसा आर्थिक समूह है जिसने वैश्विक धरातल की अर्थनीति को व्यापक तौर पर प्रभावित किया है। इस संगठन कि 2009 के बाद से निरंतर बैठकें हो रही हैं। दुनिया की आबादी का लगभग 40% हिस्सा यहाँ निवास करता है। भौगोलिक दृष्टि से सात बड़े क्षेत्रफल वाले देशों में से 4 इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व की सम्पूर्ण GDP में इनकी हिस्सेदारी लगभग 32% है। यह संगठन यद्यपि काफी तेजी से उभरता संगठन रहा है तथापि यह उभार प्रत्येक ब्रिक्स देश में देखने को नहीं मिला है। ब्राजील की औद्योगिक गति 2014 के बाद से ही ढीली है। पिछले एक दशक में ब्रिक्स के चार अन्य देशों के बनिस्बत चीन ने अपनी स्थिति को काफी हद तक मजबूत किया है। चारों देशों की तुलना में अकेले चीन की GDP दूनी है। फिर भी समग्र रूप से यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं।

वर्तमान समय में दुनिया बहुत उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। इसमें अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका बहुत अहम है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) तथा G-20 महत्पूर्ण संगठन हैं। यदि हम ब्रिक्स की बात करें तो हमें यह पता चलता है कि इसकी वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी एक चौथाई से अधिक है। जिसका 70% हिस्सा चीन के सकल घरेलू उत्पाद का है। ब्रिक्स के पिछले लगभग 20 सालों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका में व्यापार और निवेश तथा आर्थिक वृद्धि में बड़े स्तर में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। यदि हम आंकड़ों पर दृष्टि डालें तो ज्ञात होता है कि इन देशों के बीच विदेशी निवेश में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की “ब्रिक्स इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट” के अनुसार “वार्षिक एफडीआई प्रवाह 2001 से 2021 तक चौगुना से अधिक हो गया है।”



उपर्युक्त रेखाचित्र से यह स्पष्ट है कि ब्रिक्स देशों ने अपने वार्षिक एफडीआई प्रवाह में चार गुना से अधिक वृद्धि देखी है। जो एफडीआई 2001 में मात्र 84 बिलियन डॉलर था वह 2021 में बढ़कर 355 बिलियन डॉलर हो गया। इससे यह पता चलता है कि ब्रिक्स वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।



दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में हुए सम्मेलन में 6 नए देशों को ब्रिक्स में शामिल किया गया है। यह देश हैं - ईरान, इथोपिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, यूएई, और सऊदी अरब। वैश्विक जी.डी.पी. में इन देशों की हिस्सेदारी 2011 तक 20.26 प्रतिशत थी लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इन देशों ने आर्थिक स्तर पर कई मुकाम हासिल किए हैं। इसलिए साल 2023 में इन देशों की वैश्विक जी.डी.पी. में हिस्सेदारी 26.62 प्रतिशत हो गयी है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्रिक्स देश एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इन 6 देशों के मिल जाने से वैश्विक जी.डी.पी. में इनकी हिस्सेदारी 29.6 प्रतिशत तक हो जायेगी। विश्व के लगभग 30 से ज्यादा देशों ने ब्रिक्स का सदस्य बनने की इच्छा व्यक्त की है। मूल प्रश्न यह है कि क्या कारण है कि विश्व के इतने देश इस संगठन का हिस्सा बनना चाहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि विकासशील देशों के पास कोई वैश्विक आर्थिक मंच नहीं था। ब्रिक्स के उदय के बाद इन देशों को एक आर्थिक मंच मिल गया जिसके माध्यम से यह देश वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बना सकते हैं और अपनी आर्थिक समस्याओं को हल करने का प्रयास कर सकते हैं।

वैश्विक आर्थिक जगत में G-20 देशों की भूमिका

20 वीं शताब्दी का आखिरी दशक आर्थिक दृष्टि से बड़े उथल-पुथल का दशक रहा है। इस दौरान वित्तीय संकट की एक श्रृंखला शुरू हुई जिसने सोवियत रूस एवं एशिया की आर्थिक स्थिति को व्यापक तौर पर प्रभावित किया। इसने विश्व के अन्य महाद्वीपों को भी प्रभावित किया। 1990 के दशक के आखिरी सालों में वित्तीय संकटों के कारक अत्यंत जटिल और बहुआयामी थे। इस वित्तीय संकट के पीछे जो मूलभूत कारण थे उनमें प्रमुख थे- (i) मुद्रा पेग्स और निर्धारित विनियम दर (ii) अल्पकालिक विदेशी ब्याज की उच्चदर (iii) मुद्राओं पर सट्टा सम्बंधी हमले (iv) सरकारी नीतियां (v) राजनीतिक एवं सामाजिक कारक (vi) वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां। कमोवेश यही कारक एशियाई मंदी के लिए भी जिम्मेदार थे। एशियाई मुद्रा संकट जिसे बहुधा एशियाई संक्रमण भी कहा जाता है, जुलाई 1997 में शुरू हुआ। थाईलैंड में उठे इस बवंडर ने जल्द ही दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों को अपनी गिरफ्त में ले लिया।

सन 1999 में पाल मार्टिन (कनाडा के प्रधानमंत्री) और लैरी समर्स (अमेरिका उप-ट्रेजरी

सचिव) ने वैश्विक स्तर पर प्रमुख क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को लेकर एक समानान्तर अनौपचारिक समूह बनाने की आवश्यकता महसूस की। यद्यपि इस तरह का विचार सन 1994 में मैक्सिको संकट और सन 1997 की दक्षिण-पूर्व एशियाई मंदी के बाद ही आरंभ हुआ तथापि औपचारिक रूप से यह संगठन एक मंच के रूप में 25 सितम्बर 1999 को ही अस्तित्व में आ सका।

G-20 विभिन्न देशों और यूरोपियन यूनियन के केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का एक अंतरराष्ट्रीय फोरम है। इसकी स्थापना एशियाई वित्तीय संकट की प्रतिक्रिया में सन 1999 में हुई थी। इसका प्राथमिक लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देना है। G-20 समावेशित विकास और प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। जबकि इसके सदस्य देश विश्व की एक बड़ी आर्थिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह देश यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि नीतिगत चर्चाओं में विकसित एवं विकासशील देशों के दृष्टिकोण पर विचार एवं विमर्श कैसे किया जाए। यद्यपि यह विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्था नहीं है जिसके पास बाध्यकारी कानून और अधिकार हों, फिर भी यह संगठन वैश्विक आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यह आर्थिक मंच वर्ष 1999 में G-7 के वित्तमंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों, यूरोपीय संघ एवं विश्व की प्रमुख 19 अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिनिधियों की बर्लिन में हुई बैठक के बाद अस्तित्व में आया। यह एक ऐसा फोरम है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। इसका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन, अप्रवास और समावेशी विकास करना है। यह दुनिया की लगभग 80% जीडीपी, 75% व्यापार, 66% जनसंख्या तथा 60% भूभाग का प्रतिनिधित्व करता है (Jaya, 2015)।

यह आर्थिक फोरम विकसित एवं विकासशील देशों की वित्तीय समस्याओं को लेकर विचार एवं विमर्श करता है। इस संगठन में वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के माध्यम से चर्चा होती है। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका और विश्व के प्रमुख आर्थिक संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्रा कोष और विश्व बैंक विकासशील देशों की आर्थिक व्यवस्था की ताकत को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। 2008 के पूर्व तक यह संगठन उतना प्रभावी नहीं था। लेकिन हेलमैन ब्रदर्स के दिवालिया होने के बाद पूरा पश्चिमी जगत भीषण आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया। ठीक इसी वर्ष G-20 के फोरम को अपग्रेड कर वित्त मंत्रियों के सम्मेलन की जगह राष्ट्र अध्यक्षों का सम्मेलन हुआ। यह G-20 का पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन था। तब से लेकर अब तक 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं (Global Times, 10 2023)।

जब अमेरिका आर्थिक मंदी की चपेट में आया तो इस संगठन के सदस्यों ने इसकी प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना शुरू कर दिया और यह कहना शुरू किया कि भविष्य में यह संगठन आपसी आर्थिक सहयोग में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। इसी सन्दर्भ में मैक्सिको के वित्तमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि G-20 ने नई उभरती हुई अर्थव्यवस्था और संपन्न देशों के बीच बातचीत स्थापित करने में विशिष्ट भूमिका निभाई है (Marquez, 2009)। इसी क्रम में अमेरिकी सरकार के आर्थिक विभाग द्वारा जारी बयान पर ध्यान देना भी उचित प्रतीत होता है जिसमें कहा गया था कि G-20 संगठन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर बात-चीत करने का एक बेहतरीन मंच है (Sobel and Stedman, 2006)। लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों की वजह से विकासशील देशों की आर्थिक व्यवस्था में बड़े स्तर पर बदलाव हुए हैं। इस बदलाव की वजह से विकसित देशों ने भी यह सोचना शुरू किया कि विकासशील देशों की आर्थिक व्यवस्था वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के विकास में अपना अहम योगदान दे सकती है। इसलिए विकसित देशों ने विश्व के कई प्लेटफार्मों पर यह बात कही कि विकसित और विकासशील देशों

को एक साथ मिलकर विश्व की आर्थिक व्यवस्था का संचालन करना चाहिए ताकि वैश्विक समस्याओं का सही समय पर समाधान निकाला जा सके और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों पर गंभीरता से विचार विमर्श किया जा सके (Mahajan, 2023)।

ब्रिक्स एवं G-20 देशों की बदलती हुई आर्थिक ताकत

ब्रिक्स और G-20 दोनों संगठन विश्व की बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं। दोनों संगठनों ने विश्व की आर्थिक व्यवस्था को बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। G-20 का नेतृत्व यूरोपीय देशों के हाथ में है और उसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है। इसके विपरीत ब्रिक्स देशों में तीन बड़े खिलाड़ी हैं जो अपनी भूमिका निभाने के लिए उद्यमशील हैं। यह देश क्रमशः चीन, भारत एवं रूस हैं। पूर्णरूपेण तो नहीं फिर भी यह कहने में कोई संशय नहीं है कि चीन फिलहाल ड्राइविंग सीट पर है। G-20 का एक बड़ा समुदाय अमेरिका की वैचारिकी को आगे बढ़ा रहा है। बदलते हुए दौर में जब वैश्विक फलक पर संघर्ष का केंद्र ऊर्जा और आर्थिक ताकत के संवर्धन पर है तो विश्व की दो बड़ी शक्ति चीन और अमेरिका के मध्य वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापन का खेल जारी है। चीन मुख्य रूप से ब्रिक्स के संगठन में बड़े स्तर पर आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। चीन ब्रिक्स देश के साथ-साथ अन्य देशों को भी आर्थिक सहायता प्रदान करता है। ब्रिक्स के माध्यम से चीन का उद्देश्य यह है कि वह यूरोप के साथ-साथ अमेरिका के वर्चस्व को वैश्विक स्तर पर कैसे चुनौती दे। जिस तरीके से चीन की आर्थिक ताकत बढ़ रही है उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले 50 सालों में चीन विश्व का सबसे ताकतवर देश बन सकता है, जो वैश्विक स्तर पर अमेरिका और यूरोपीय देशों के प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है (Sawhney, 2023)।

यदि पिछले 30 सालों के विदेशी निवेश पर दृष्टिपात करें तो यह विदित होता है कि सन 1995 में G-20 देशों का विदेशी निवेश कुल वैश्विक विदेशी निवेश (FDI) का 44.9% था जबकि ब्रिक्स देशों का विदेशी निवेश मात्र 16.9% था। लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत से ही ब्रिक्स देशों ने आर्थिक नीतियों में बड़े स्तर पर बदलाव कर लिए जिसकी वजह से 2010 में ब्रिक्स देशों का विदेशी निवेश (FDI) 16.9% से बढ़कर 26.6% पहुँच गया जबकि वहीं G-20 देशों का विदेशी निवेश घटकर 34.3% रह गया। सन 2010 से लेकर 2023 तक विश्व की आर्थिक नीतियों में कई बदलाव हुए हैं जिसने विश्व के आर्थिक ढांचे को प्रभावित किया है। इसका प्रभाव ब्रिक्स और G-20 देशों के विदेशी निवेश में भी देखने को मिला है। इस काल में ब्रिक्स देशों ने G-20 देशों को विदेशी निवेश के मामले में काफी पीछे छोड़ दिया जो आर्थिक दृष्टि से एक क्रांतिकारी बदलाव है और यह भी इंगित करता है कि अब G-20 देश नहीं बल्कि ब्रिक्स देश विश्व के आर्थिक जगत का नेतृत्व करेंगे (तालिका न.1)।

तालिका 1: ब्रिक्स एवं G-20 का विदेशी निवेश (FDI)

वर्ष	ब्रिक्स	G-20
1995	16.9%	44.9%
2010	26.6%	34.3%
2023	32.1	29.9%

Source: IMF World Economic Outlook (2023 data based on IMF estimates as of April 2023)

ब्रिक्स एवं G-20 जैसे आर्थिक संगठनों में भारत की भूमिका

21वीं सदी में विश्व के आर्थिक ढांचे में बड़े स्तर पर बदलाव हो रहा है जिसका प्रभाव विश्व की राजनीति पर भी दिख रहा है। जो देश आर्थिक रूप समृद्ध हैं वह विश्व के विकासशील देशों के साथ अपने संबंध सुधार रहे हैं ताकि उनकी आर्थिक तरक्की हो सके। इस बदलते परिवेश में भारत को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे वह अपने आर्थिक हितों की रक्षा बड़े स्तर पर कर सकता है। चूंकि भारत इन दोनों संगठनों का सदस्य है इसलिए भारत को दोनों ही मंचों के साथ संतुलन बनाकर विश्व राजनीति के ध्रुवीकरण से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए जिससे विश्व का समुचित विकास हो सके और दुनिया के विभिन्न देश वैश्विक चुनौतियों जैसे कि पर्यावरण और आतंकवाद की समस्या का समाधान करने में सफल हो सकें। यह भारतीय विदेश नीति का सैद्धांतिक पक्ष है जिस पर भारत लगातार जोर देता है, किन्तु विश्व राजनीति का व्यावहारिक पक्ष एकदम अलग है जिसकी बारीकियों को समझना भारतीय विदेश नीति के विश्लेषकों की सोच एवं समझदारी पर निर्भर है। प्रवीण साहनी भारत की ब्रिक्स और G-20 की भूमिका का अध्ययन करने के बाद यह कहते हैं कि ब्रिक्स गतिशील और विकसित हो रहा है और विश्व की उभरती हुई अन्य आर्थिक शक्तियों को आकर्षित कर रहा है। जबकी G-20 जो G-7 से विकसित हुआ वह बिना चीन और रूस के बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं रहेगा। यदि भारत कोई गलत रास्ता चुनता है तो इसका खामियाजा इसे भविष्य में भुगतना पड़ सकता है (Sawhney, 2023)। जबकि प्रवीण साहनी के अलावा एक अन्य विश्लेषक अंतरा घोसल सिंह की धारणा है कि ब्रिक्स का विस्तार करने का चीन का उद्देश्य ब्रिक्स तंत्र और मंच के माध्यम से अपने “एजेंडे और भव्य रणनीति” को अधिक मजबूती से बढ़ावा देना और कूटनीतिक रूप से अमेरिका की रोकथाम को आसान बनाना है। चीन ब्रिक्स को एंटी-अमेरिका के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है (Singh, 2022)। चीन यह भी चाहता है कि ब्रिक्स के अगले विस्तार में पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल किया जाए। यदि पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल किया जाता है तो यह भारत के हितों की रक्षा के लिए एक चिंता का विषय होगा (Jha, 2023)। आर्थिक दृष्टि से भारत की G-20 और ब्रिक्स में क्या भूमिका है उसे तालिका 2 तथा 3 से स्पष्ट किया गया है।

तालिका 2: भारत का जी-20 के साथ का कुल आयात और निर्यात (2018-19 से 2022-23)

निर्यात		
वर्ष	मिलियन (\$)	कुल निर्यात का %
2018-19	145,086.45	43.95%
2019-20	142,684.09	45.53%
2020-21	144,179.42	49.40%
2021-22	209,528.70	48.93%
2022-23	212,926.09	47.20%
आयात		
वर्ष	मिलियन (\$)	कुल आयात का %
2018-19	257,741.80	50.13%
2019-20	241,698.65	50.91%
2020-21	207,202.99	52.53%
2021-22	311,266.02	50.77%
2022-23	393,770.59	54.99%

Source: वित्त मंत्रालय द्वारा जारी प्रदत्त के आधार पर शोधार्थी का विश्लेषण

तालिका 2 का विश्लेषण करने पर विदित होता है कि 2018-19 में पूरी दुनिया के साथ हुए निर्यात का 43.95% G-20 के देशों के साथ था जो मामूली वृद्धि के साथ 2022-23 में 47.20% हो गया। आयात में भी कोई बहुत वृद्धि नहीं देखी गई है। परंतु व्यापार घाटे की समस्या G-20 के साथ यथावत है जो भारत के लिए चिंताजनक है। यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस विश्लेषण में यूरोपीय संघ को सम्मिलित नहीं किया गया है।

तालिका 3: भारत का ब्रिक्स देशों के साथ का कुल आयात और निर्यात (2018-19 से 2022-23)

निर्यात		
वर्ष	मिलियन (\$)	कुल निर्यात का %
2018-19	27,009.37	8.18%
2019-20	27,705.99	8.84%
2020-21	32,021.80	10.97%
2021-22	37,088.74	8.78%
2022-23	36,846.95	8.16%
आयात		
वर्ष	मिलियन (\$)	कुल आयात का %
2018-19	87,083.84	16.93%
2019-20	82,398.52	17.35%
2020-21	81,282.18	20.60%
2021-22	121,119.65	19.75%
2022-23	161,788.83	22.59%

Source: वित्त मंत्रालय द्वारा जारी प्रदत्त के आधार पर शोधार्थी का विश्लेषण

इसी प्रकार तालिका 3 में वर्णित 2018-19 से 2022-23 तक भारत का ब्रिक्स देशों के साथ कुल आयात और निर्यात का विश्लेषण करने से पता चलता है कि भारत का आयात लगातार ब्रिक्स से बढ़ रहा है जो वित्तीय वर्ष 2018-19 में जहां पूरे विश्व के आयात का सिर्फ 16.93% था वहीं 2022-23 में बढ़कर 22.59% पहुंच गया है। जबकि भारत का ब्रिक्स देशों के साथ निर्यात में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला वरन् 2018-19 की तुलना में 0.02% घटा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अनुचित है। भारत को अपने व्यापार घाटे को संतुलित करना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत संप्रति ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से उसे अपने भू-राजनीतिक विकल्प की तलाश करने में बड़ी कठिनाई हो रही है। इसके पीछे जो प्रत्यक्ष कारण दिखलाई पड़ता है वह यह है कि उसे एक ही साथ

G-20, क्वॉड, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन में अपनी विशिष्ट भूमिका निभानी है। ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन और वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) जैसे गैर पश्चिमी संगठन में भारत की बढ़ती अभिरुचि का कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रेटन वुड्स समझौते के फलतः अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और 44 अन्य देशों बैंक (WB) की अलोकतांत्रिक तथा असमान संरचना से विकर्षण है। इसका निहितार्थ यह भी नहीं है कि भारत पश्चिम के विरुद्ध है और यह होना भी नहीं चाहिए।

भारत का ग्लोबल साउथ, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग से जुड़ाव ऐतिहासिक, भौगोलिक और विकासवात्मक दृष्टि पर आधारित है। शीत युद्ध के युग में भारत तीसरी दुनिया के देशों का गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसे फोरम पर नेतृत्व कर रहा था किन्तु बदलती हुई भू-आर्थिकी ने भारत को पुराने सम्बन्धियों के साथ ही नए क्षेत्र से जुड़ने पर विवश कर दिया। इस प्रकार भारत पहली बार बड़े देशों के क्लब में सम्मिलित हुआ। W.T.C. के बाद अमेरिका से निकटता बढ़ गई फिर उसने क्वॉड और G-20 के साथ ही G-7 की बैठकों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इतना सब होने के बावजूद वह न तो पश्चिम और न ही ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने की स्थिति में है क्योंकि इन दोनों मंचों का नेतृत्व फिलहाल क्रमशः अमेरिका और चीन के हाथ में है। फलतः भारत एक उभरते हुए भू-राजनीतिक क्षितिज को निर्निमेष भाव से देख रहा है और इस तलाश में है कि वहां तक कैसे पहुंचे? भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक दृष्टि से दोनों मंचों पर एक साथ बने रहना उसकी प्राथमिकता में है। एक और मौलिक संकट हाल के वर्षों में भारतीय कूटनीतिज्ञों के समक्ष उपस्थित हुआ है वह है दो प्रतिस्पर्धी गुटों का उदय। यह स्थिति लगभग शीत युद्ध जैसी है जहाँ एक ओर अमेरिका है तो दूसरी ओर चीन और रूस। रूस उस चरमोत्कर्ष वाली स्थिति की तलाश में है जो कभी 1990 के पहले थी। चूंकि अमेरिका उसका परंपरागत शत्रु है और वर्तमान में चीन भी अमेरिका के समक्ष मुखर है। अतः दोनों के मध्य काफी निकटता आ गई है। रूस का अचानक से चीन के पाले में जाना भारतीय विदेश नीति के विश्लेषण के लिए चिंता की बात है।

भारत ने अपनी पुरानी गुटनिरपेक्षता की नीति को एक नए कलेवर में प्रस्तुत करते हुए ग्लोबल साउथ के साथ जुड़ना बेहतर समझा है। पुनः जनवरी 2023 में दिल्ली में “वाॅइस ऑफ ग्लोबल साउथ” का आयोजन किया गया (Bhattacharjee, 2023)। इसके बाद G-20 की बैठक के दौरान भारत ने ग्लोबल साउथ के 11 देशों और अफ्रीकी यूनियन को भी आमंत्रित कर G-20 को G-21 में तब्दील कर दिया। इस प्रकार भारत ने अपने परंपरागत विदेश नीति के गुटनिरपेक्ष सिद्धांत को यथावत रखते हुए दोनों गुटों के साथ अपनी स्थिति के अनुरूप अपने सम्बंधों को बेहतर करने की कोशिश की है। इसे चीन के उस कार्य की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है जिसमें ब्रिक्स की जोहानसबर्ग की बैठक में चीन के आमंत्रण पर 35 अफ्रीकी देश जुड़े थे। दिल्ली बैठक में ग्लोबल साउथ की उपस्थिति ने विकासशील और गरीब देशों की चिंता को केंद्र में रखकर भारत ने पश्चिमी शक्तियों को चुनौती दी है (Sharma, 2023)।

उपर्युक्त विवेचना के आलोक में कहा जा सकता है कि भारत को अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के निमित्त दोनों संगठनों के साथ सम्बंध बनाए रखना होगा। ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने का दावा चीन भी करता है। अतः भारत को ग्लोबल साउथ के देशों में अपनी विश्वास बहाली करनी होगी। उन्हें इतिहास में झांकने के लिए विवश करना होगा ताकि वह चीन के वास्तविक दृष्टिकोण से परिचित हो सकें और चीन द्वारा निर्मित मकड़ जाल में फंसने से बच सकें। इस प्रकार भारत इन देशों में यह भावना जागृत कर पाने में सफल हो सकेगा कि ग्लोबल साउथ का वास्तविक नेतृत्व वह ही कर सकता है। भारत को अपनी आर्थिक स्थिति के विकासवात्मक ढांचे को तो सुदृढ़ करना ही होगा लेकिन यह बदलाव वैश्विक

पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए करना होगा, साथ ही चीन के ओबोर प्रोजेक्ट (OBOR Project) को यथाशीघ्र चुनौती देते हुए IMEC, चाबहार पोर्ट और INSTC पर भी तेजी से कार्य करना होगा। वस्तुतः आर्थिक समृद्धि के साथ ही सतत विकास, हरित पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों के समाधान को भी खोजना होगा।

संदर्भ सूची

- Abrams, E. (2022, March 4). The New Cold War. Retrieved from Council on Foreign Relations: <https://www.cfr.org/blog/new-cold-war-0>
- Bhatt, A. (2023, October 4). No One Knows What BRICS Expansion Means. Retrieved from <https://thediplomat.com/2023/10/no-one-knows-what-brics-expansion-means/>
- Bhattacharjee, K. (6 January, 2023). India to host Voice of the global south summit. The Hindu.
- Global Times, 10 September, 2023.
- Global Times, 24 August, 2023
- Jaya, R. (2015, September 9). G-20 finance ministers committed to sustainable development. Retrieved from ipsnews.net/2015/09/g-20-finance-ministers-V.Rubio-development-committed-to-sustainable-Marquez
- Jha, V. (2023, August 25). Brics kavistaraurcheenkibdhteetakatbharatkeliyechintaki bat. Retrieved from Jansatta.com
- Mahajan, A. (2023, September 6). Brics men Badhtee any deshonkidilchspee. Retrieved from prabhatkhabar.com
- Marquez V. R. (2009). A Practitioners Perspective. In N. W. LeonardoMartinez-Diaz. Oxford University Press.
- Sawhney, P. (2023, September 4). BRICS is Dynamic, the G20 is Not. Retrieved from <https://thewire.in/world/brics-is-dynamic-the-g20-is-not>
- Sharma, A. (2019, 18 June). Brics :Samajik-ArthikSahyogkaekdashak.Indian Council of World Affairs (Government of India) (icwa.in)
- Sharma, P. (19 sep 2023). How the global south sized the spotlight at G 20 summit in new delhi. The Hindu.
- Singh, A. G. (2022, July 21). Why China wants to expand BRICS. Retrieved from www.orfonline.org/expert-speak/why-china-wants-t-expand-brics/
- Sobel, M. &. (July 2006). The Evolution of the G-7 and Economic Policy Coordination (Occasional paper no 3). US Department of the Treasury, office of International Affairs.
- Tripathi, S.P.M. (2021). AntarrashtreeySangathan. New Delhi: Raj Publication.

मेकल मीमांसा

(ISSN-0974-0118)

मेकल मीमांसा: एक परिचय

सन 2009 में आरंभ मेकल मीमांसा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक, मध्य प्रदेश द्वारा प्रकाशित डबल ब्लाइंड पीअर रिव्यूड शोध पत्रिका है। राष्ट्रभाषा हिंदी में प्रकाशित अर्धवार्षिक शोधपत्रिका हेतु ज्ञान-विज्ञान के सभी क्षेत्रों से मौलिक शोध प्रकाशन हेतु आमंत्रित किया जाता है। शोध पत्रिका का उद्देश्य शोधार्थियों, नीति नियामकों, एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों के ज्ञानवर्धन तथा संवर्धन हेतु उपयोगी नवोन्मेषी, मौलिक और नूतन शोध को सामने लाना है। प्रकाशन में उच्च मानकों को बनाए रखने हेतु पत्रिका के लिए एक निर्धारित, वस्तुनिष्ठ ब्लाइंड पीअर रिव्यू पद्धति से शोध पत्रों का चयन किया जाता है।

पत्रिका का उद्देश्य एवं क्षेत्र-

मेकल मीमांसा शोध पत्रिका का मूल उद्देश्य राष्ट्रभाषा हिंदी में गुणवत्तायुक्त मौलिक शोध को सामने लाना है। पत्रिका सैद्धांतिक, अनुप्रयुक्त एवं नीति निर्धारण आदि सभी क्षेत्रों में होने वाले अनुसन्धान को प्रकाशित करने का कार्य करती है। पत्रिका का विशेष आग्रह आदिवासी विकास, संस्कृति एवं जीवन पद्धति आदि से जुड़े स्तरीय, वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक शोध के प्रकाशन के प्रति है।

पत्रिका की सदस्यता हेतु सहयोग राशि

क्रम संख्या	श्रेणी	अवधि	सहयोग राशि रूपयों में
1	संस्थागत सदस्यता हेतु	अर्धवार्षिक	300.00
		वार्षिक	550.00
		आजीवन	5000.00
2	व्यक्तिगत सदस्यता हेतु	अर्धवार्षिक	250.00
		वार्षिक	475.00
		आजीवन	4500.00
3	आन्तरिक व्यक्तिगत सदस्यता एवं शोधार्थियों हेतु	अर्धवार्षिक	200.00
		वार्षिक	350.00
		आजीवन	3250.00

सहयोग राशि का भुगतान ऑनलाइन/बैंक ट्रांसफर के माध्यम से स्वीकार किया जाता है। बैंक डिटेल हेतु सम्पादकीय टीम से संपर्क किया जा सकता है।

मेकल मीमांसा के आगामी अंको हेतु शोध पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। शोध पत्र मौलिक, वस्तुनिष्ठ एवं ज्ञान के क्षेत्र और समाज तथा संस्कृति के संवर्धन में योगदान करने में सक्षम हों। मौलिकता प्रमाणपत्र एवं अन्यत्र प्रकाशन हेतु नहीं भेजे जाने सम्बंधी घोषणा के साथ शोध पत्र mekalmimansa@igntu.ac.in पर ई-मेल किए जा सकते हैं। विस्तृत निर्देश हेतु हमारी वेबसाइट देखें।

<http://www.igntu.ac.in/mekalmimansa.aspx>



इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक (म.प्र.)



मेकल मीमांसा

अंतर-अनुशासनात्मक डबल ब्लाईंड पीयर रिव्यूड यूजीसी केयर सूचीबद्ध अर्धवार्षिक शोध पत्रिका

<http://www.igntu.ac.in/mekalmimansa.aspx>